

वशेष न्यायालय

प्रलिमिन्स के लिये:

वशेष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नविवरण) संशोधन अधिनियम, 2015

मेन्स के लिये:

वशेष न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वधायकों की त्वरति जाँच के लिये वशेष न्यायालय की स्थापना हेतु **राज्य-वशिष्ट दृष्टिकोण** का सुझाव दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" दृष्टिकोण सांसदों और वधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबति समस्या को हल नहीं कर सकता है क्योंकि प्रत्येक राज्य में **वादों की संख्या अलग-अलग है**।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सांसदों के लंबे समय से लंबति मुकदमों को तेज़ी से ट्रैक करने के लिये देश भर में वशेष अदालतें स्थापति की जाएँ।
 - इसके बाद 11 राज्यों में वशेष रूप से मौजूदा सांसदों और वधायकों की सुनवाई के लिये 12 वशेष न्यायालय स्थापति किये गए।
- संतिंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयिकृत [\[1\]\[2\]\[3\]\[4\]\[5\]\[6\]\[7\]\[8\]\[9\]\[10\]\[11\]\[12\]\[13\]\[14\]\[15\]\[16\]\[17\]\[18\]\[19\]\[20\]\[21\]\[22\]\[23\]\[24\]\[25\]\[26\]\[27\]\[28\]\[29\]\[30\]\[31\]\[32\]\[33\]\[34\]\[35\]\[36\]\[37\]\[38\]\[39\]\[40\]\[41\]\[42\]\[43\]\[44\]\[45\]\[46\]\[47\]\[48\]\[49\]\[50\]\[51\]\[52\]\[53\]\[54\]\[55\]\[56\]\[57\]\[58\]\[59\]\[60\]\[61\]\[62\]\[63\]\[64\]\[65\]\[66\]\[67\]\[68\]\[69\]\[70\]\[71\]\[72\]\[73\]\[74\]\[75\]\[76\]\[77\]\[78\]\[79\]\[80\]\[81\]\[82\]\[83\]\[84\]\[85\]\[86\]\[87\]\[88\]\[89\]\[90\]\[91\]\[92\]\[93\]\[94\]\[95\]\[96\]\[97\]\[98\]\[99\]\[100\]](#) ने अपनी दो रपिर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि वधायकों के खलिाफ मामलों की सुनवाई के लिये न्यायालय द्वारा वशेष न्यायालयों का गठन करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मौजूदा 2,556 संसद (सांसद) और वधिान सभाओं के (वधायक) सदस्यों से जुड़े 4,442 आपराधिक मामले लंबति हैं।
 - इन मामलों की संख्या अब 5,000 का आँकड़ा पार कर चुकी है, जनिमें से 400 जघन्य अपराधों से संबंधति हैं।

वशेष न्यायालय:

- परचिय:**
 - वशेष न्यायालय एक सीमति कषेत्राधिकार वाला न्यायालय है जो किसी वशेष कषेत्रीय वार्ड के बजाय कानून के एक नशिचति कषेत्र से संबंधति होता है। भारत में इन न्यायालयों की स्थापना **वशेष न्यायालय अधिनियम, 1979** के तहत की गई है।
 - भारत में वशिष्ट प्रकार के मामलों से नपिटने हेतु वभिन्नि वशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय त्वरति न्याय प्रदान करने और कुछ प्रकार के मामलों से जुड़ी अद्वितीय कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के लिये स्थापति किये गए हैं।
- कषेत्राधिकार:**
 - वशेष कषेत्राधिकार** कुछ प्रकार के मामलों पर न्यायालयों का अधिकार कषेत्र है, जैसे दविलयिापन, सरकार के खलिाफ दावे, प्रमाणति वसीयत, पारविवारिक मामले, आप्रवासन और सीमा शुल्क या अधिकितम राशा या मूल्य वाले मामलों में न्यायालयों के अधिकार पर सीमाएँ। वशेष कषेत्राधिकार को सीमति कषेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है।
 - वशेष न्यायालय बहुत ही सीमति कषेत्राधिकार के तहत मामलों की सुनवाई करता है और इसके न्यायाधीश एक वशिष्ट अवधा के लिये ही कार्य करते हैं, जबकि संवैधानिक न्यायालय का मुख्य अधिकार यह तय करना है कि जनि कानूनों को चुनौती दी गई है, क्या वे असंवैधानिक हैं, उदाहरण के लिये संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ वशिधाभाषी हैं।

अन्य संबंधित पहलें:

- [POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायालय](#)
- [फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये योजना](#)
- [ई-न्यायालय एकीकृत मशिन मोड परियोजना](#)

आगे की राह

- चूँकि राजनीति नौकरशाही पर हावी है और व्यापार, नागरिक समाज और मीडिया पर लगाम लगाती है, इसलिये देश को ऐसे शासन की आवश्यकता है जो "आपराधिक" वायरस से मुक्त हो।
- जनता के दबाव से अभियोजन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यदि एक राजनीतिक दल को बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो यह सकारात्मक कदम हो सकता है।

[स्रोत: द दृष्टि](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-courts-4>

